

This question paper contains 3 printed pages]

HPAS (Main)—2017

PUBLIC ADMINISTRATION

Paper II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note :— Attempt five questions in all. Question No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. How have the relations between the Centre and the States in India evolved over the years ?

भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध वर्षों से कैसे विकसित हुए हैं ?

2. Analyse the role, powers and functions of *Parliamentary Standing Committees* in India.

भारत में संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका, अधिकार और प्रकार्य का विश्लेषण कीजिए।

P.T.O.

3. Write an essay on the structure and functions of the office of *Comptroller and Auditor General of India* and its role as a Nation's Conscience Keeper.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की संरचना और प्रकार्य और इसकी राष्ट्र के विवेक रक्षक की भूमिका पर लेख लिखिए।

4. Discuss the following :

(a) Lateral Entry

(b) Relationship between Secretariat and Directorate

निम्न की विवेचना कीजिए :

(अ) लेटेरल प्रविष्टि

(ब) सचिवालय और निदेशालय में संबंध

5. How is NITI Aayog different from Planning Commission and analyze the rationale for its setup ?

नीति आयोग, योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है और इसकी स्थापना के तर्क का विश्लेषण कीजिए।

6. Examine the recommendations of 2nd Administrative Reforms Commission on functions of District Collector.
जिलाधिकारी के प्रकार्यों के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों का मूल्यांकन कीजिए।

7. What challenges are being faced by the *Public Sector Enterprises* in India today and what is the disinvestment policy of the government in the sector ?

आज भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सरकार की इस क्षेत्र में विनिवेश नीति क्या है ?

8. Assess the impact of :

(a) Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 in delivery of public services to the citizens.

(b) Sustainable Plastic Waste Management in Himachal Pradesh

निम्न के प्रभाव का आकलन कीजिए :

(अ) नागरिकों को लोक सेवाएँ वितरण में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011

(ब) हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का सतत प्रबंधन